[Shri Vayalar Ravi]

in support of their demands. As the House is aware, the Central Government employees are clamouring to settle their pending demands since a long time. Unfortunately none of their representations have been heard or any decision taken on their charter of demands. The Central Government employees, including railwaymen, Posts & Telegraphs, Defence, Audit & Accounts and others numbering 30 unions, have jointly taken the decision to launch a nation-wide agitation.

Many issues of the Railwaymen including bonus are still pending. The P & T employees are so much ignored and many of the recommendations of the Pay Commission have not been implemented properly. There is no proper machinery to look into the grievances of the P & T employees and rather the Government is more eager to ignore mutual discussions. It has become the practice on the part of the authorities to implement arbitrary decisions. 30 per cent of the P & T employees numbering more than 2 lakhs are extra-departmental employees. They are still considered as outsiders and getting only the lowest remuneration in the country. They do not have any benefit of being Government employees even though they work more than a Government servant. The condition of extra departmental employees is a mere reflection of slavery and it is high time they are absorbed in regular service.

The Central Government employees are legitimately demanding the merger of Dearness Allowance with basic pay. There are many cases of victimization still pending, which were initiated in 1968. A large number of casual workers, contract labour, etc. are still continuing by the government and the employees are demanding abolition of these systems. Direct recruits to certain categories are creating a stagnation and are blocking the promotional avenues of lower grade employees.

All these demands of the Central Government employees are of a serious nature and require immediate attention of the Government, but, unfortunately, the Government is reluctant to have any negotiations or a dialogue with the representatives of the Central Government employees to settle these issues. Any delay on the part of the Government will aggravate the situation and it will lead to a countrywide agitation by the Central Government employees and the Government will be fully responsible for any such situation. So, I take this opportunity to demand from this Government to start a dialogue with the representatives of the Central Government employees immediately and settle the problems.

(ii) REPORTED SMUGGLING OF JUTE TO NEPAL

श्री लखन लाल कपूर (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं।

यह सर्व विदित है कि भारत के 6 राज्यों में पटसन का उत्पादन होता है—जैसे बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, आंध्र और त्रिपुरा। यह भी सर्वविदित है कि विगत वर्ष में पटसन का उत्पादन जरूरत से बहुत कम हुआ जिसके कारण पटसन उद्योग बन्द ही रहे हैं।

भारत के पटसन उद्योग को चालू रखने और मजदूरों को काम देने के लिए थाईलैंड और दक्षिण पूर्व के अन्य देशों से पटसन आयात किया जाता है और मिल-मालिकों को सब्सीडाइज्ड रेट्स पर पटसन दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां एक ओर पटसन की कमी के कारण हमारे उद्योग बंद हो रहे हैं, वहां दूसरी ओर हमारे मजदूर भी बेकार हो रहे हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकारी कर्मचारियों की स्मगलर्स के साथ सांठगांठ से हमारा पटसन का बहुत सा उत्पादन देश से बाहर भी जा रहा है। बिहार के पूर्णिया और सहर्सा में पटसन

का उत्पादन अधिक होता है । वहां का बहुत सा उत्पादन देश से बाहर चला जाता है ।

मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में ज्यादा कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय मामला है । नेपाल के साथ भारत की सीमा खुली है । उस सीमा पर हमारे कस्टम अधिकारियों की कनाइवेंस से स्मगलर्स बहुत सा पटसन नेपाल भेज देते हैं । हमें विश्वस्त सूत्रों से खबर मिली है कि जे० सी० आई० के अधिकारियों के मना करने पर भी बहुत सा पटसन इस देश से बाहर जा रहा है । इन अधिकारियों के मना करने पर भी कस्टम अधिकरियों ने 6 लाख मन पटसन भारत से नेपाल भिजवाया है जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए होती है । इस सम्बन्ध में जे० सी० आई० के अधिकारियों ने सरकार को सूचना दी, खबर दी, लेकिन चुंगी अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । बल्कि सीमा पर स्वयं खड़ा होकर पटसन स्मगल करवाया है ।

अभी भी वहां यह स्थिति है कि बार्डर पर जो इलाके हैं, उनमें व्यापारियों के पास बहुत-सा पटसन है जो कि नेपाल भेजा जा रहा है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस तरह से जो फारन एक्सचेंज की हानि होती है, उसे रोकने के लिए बार्डर पर अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए । बार्डर को सील करना चाहिए और इसकी रोकथाम बार्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा करायी जानी चाहिए ।

पटसन की स्मगलिंग से हमारे मिल बंद हो रहे हैं, हमारे मजदूर बेकार हो रहे हैं । नेपाल बार्डर पर यह जो स्मगलिंग होता है, उसकी इंकवायरी सी० बी० आई० के द्वारा करायी जाए, यह मेरी मांग है । सी० बी० आई० को यह मामला सौंपना चाहिए जिससे यह पता चल सके कि कैसे भारत-नेपाल सीमा पर पटसन का स्मगलिंग होता है और किन लोगों की साठगांठ से यह होता है । इस इंकवायरी से यह भी पता चलेगा कि कितना पटसन का उत्पादन नेपाल में होता है और कितना पटसन नेपाल से बाहर भेजा जाता है । नेपाल का पटसन जोगबनी रेलवे स्टेशन से होकर ही बाहर जाता है ।

इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इस पर अविलम्ब कार्यवाही करे और जो अधिकारी लोग दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें ।

(iii) REPORTED LABOUR UNREST IN FARIDABAD AND DELHI INDUSTRIAL COMPLEX.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): Mr. Deputy Speaker, under Rule 377 of the Rules of procedure and Conduct of Business I want to draw the attention of the House to an urgent matter and to request the Minister concerned to make a statement—

"Severe labour unrest in Faridabad and Delhi Industrial Complex particularly in Autopin and allied group of industries following the management's terrorism including display of firearms and employing goondas even hired from out side the state as security guards to intimidate the workers has become the rule of industrial magnet in Faridabad and Delhi. This is even confirmed by the Deputy Superintendent of police Faridabad, as reported in the newspaper."

In this connection I want to quote the news in The Times of India and other newspapers, of February 21, 1978. The news in The Times of India is—

"The Deputy Suprintendent of Police, Mr. Jai Singh, to-day confirmed that three of the security guards involved in a clash with striking workers of an engineering factory in the New Industrial Township on